फाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय (एयू)/ई6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में सितंबर,2023 माह का मासिक सारांश ।

सितंबर, 2023 माह के लिए न्याय विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. भारत गणराज्य के उच्चतम न्यायालय और सिंगापुर गणराज्य के उच्चतम न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन

दिनांक 6.9.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य के उच्चतम न्यायालय और सिंगापुर गणराज्य के उच्चतम न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 7.9.2023 को सिंगापुर में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश श्री सुंदरेश मेनन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

2. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 13.09.2023 को 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चार साल (2023 से आगे) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण-III को मंजूरी दे दी। चरण-I और चरण-II के लाभ को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-कोर्ट चरण-III का लक्ष्य डिजिटल ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है। चरण-III का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफ़ेस प्रदान करेगा। ई-कोर्ट चरण-III की महत्वपूर्ण विशेषताओं में संपूर्ण अदालती रिकॉर्ड अत्यधिक पुराने और लंबित मामले दोनों,का डिजिटलीकरण, आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा रिपॉजिटरी; है। बिना कंप्यूटर लॉजिस्टिक्स वाले या जो कंप्यूटर के अनुकूल नहीं हैं, उन नागरिकों तक आसान पहुंच प्रदान करके डिजिटल खाई को पाटने के लिए सम्पूर्ण भारत के सभी न्यायालय परिसरों में संतृप्ति मोड पर ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही और मामलों के त्वरित निपटान आदि के लिए अदालती कार्यवाही को डिजिटल प्रारूप के तहत लाने के लिए सभी वाणिज्यिक न्यायालयों सहित कागज रहित न्यायालय शामिल हैं ।

3. ई-कोर्ट परियोजना के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर शामिल उच्चतम न्यायालय

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 14.09.2023 को घोषणा की कि भारत के उच्चतम न्यायालय के डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर शामिल किया गया है, जो तालुका स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अदालतों में लंबित मामलों और निपटान दर से संबंधित डेटा का भंडार है। यह घोषणा करते हुए कि शीर्ष अदालत के मामले वास्तविक समय के आधार पर एनजेडीजी पर अपलोड किए जाएंगे, सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर डेटा अपलोड करने से न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी ।

4. स्वछता ही सेवा (एस.एच.एस.) 2023 और स्पेशल अभियान 3.0

"कचरा मुक्त भारत" की थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान (एसएचएस-2023) के तहत न्याय विभाग ने विभिन्न गतिविधियां शुरू कीं । विभागीय कार्यालय परिसर में हरा गीला सूखा नीला-2 कूड़ेदान प्रणाली शुरू की गई, विभाग के सभी स्टाफ सदस्यों ने स्वच्छता शपथ ली, एसएचएस 2023 का बैनर विभाग की वेबसाइट पर लगाया गया और 1 अक्टूबर, 2023 को नियमित और संविदा कर्मचारियों द्वारा एक घंटे के श्रमदान के साथ शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत के उच्चतम न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी इस राष्ट्रीय अभियान में भाग लिया है और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में कई गतिविधियाँ आयोजित की हैं ।

विशेष अभियान 3.0 (15-29 सितंबर) के प्रारंभिक चरण के तहत, विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की है। इस अवधि के दौरान, सांसदों से प्राप्त निर्देशों के संबंध में कुल लंबन संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों और निपटान के लिए तैयार स्क्रैप सामग्री की पहचान की गई है। डीएआरपीजी पर दैनिक स्थिति अपलोड की जा रही है। अगले चरण (2-31 अक्टूबर, 2023) के दौरान, सभी पहचाने गए लंबित मामलों को निपटाया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जाएगा और बेहतर कार्य परिवेश बनाने के लिए जगह खाली की जाएगी।

5. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-II:

क. **एनजेडीजी:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर, दिनांक 01.09.2023 तक, 23.81 करोड़ से अधिक मामलों और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ख. **वर्चुअल कोर्ट:** 24 वर्चुअल कोर्ट द्वारा 3.62 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और दिनांक 31.08.2023 तक 41 लाख से अधिक मामलों में444.96 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। दो नए वर्चुअल कोर्ट (एक गुजरात में और एक उत्तराखंड में) शुरू किए गए हैं और वर्चुअल कोर्ट की कुल संख्या 24 हो गई है ।

ग. **जस्टिस ऐप:** न्यायिक अधिकारियों के लिए मोबाइल ऐप को 31 अगस्त, 2023 तक कुल 19,288 व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया गया है ।

घ. **ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप:** ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की संख्या दिनांक 31.08.2023 तक कुल 1.99 करोड़ तक पहुंच गयी है।

ङ. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** 31 अगस्त 2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके 2.84 करोड़ मामलों (जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 2.05 करोड़ मामले, और उच्च न्यायालयों द्वारा 79 लाख मामले) की सुनवाई की गई ।

च. **ई-सेवा केंद्र:** दिनांक 31.08.2023 तक 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 851 ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक बनाए जा चुके हैं

6. टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंचना

क. 30 सितंबर, 2023 तक, सितंबर, 2023 के महीने में 2,72,540 लाभार्थी सहित 52.99.154 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई।

ख. सितंबर माह के दौरान, ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई)/पैरा कानूनी स्वयंसेवकों (पीएलवी), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों के 120 जिलों में आयोजित 168 जागरूकता सत्रों/शिविरों में 3407 लोगों ने भाग लिया।

ग. वीएलई, पैनल वकील, राज्य समन्वयक जैसे टेली-लॉ क्षेत्र के पदाधिकारियों के अनुभवों को साझा करने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम के सेल्फी ड्राइव अभियान के तहत 30 सितंबर, 2023 तक 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 203 सेल्फी/वीडियो टेली लॉ सोशल मीडिया साइटें (फेसबुक और ट्विटर) पर अपलोड किए गए थे ।

7. न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम:

माह महीने के दौरान, 76 नए प्रो-बोनो अधिवक्ताओं ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया। न्याय बंधु पोर्टल के तहत कुल 10454 वकील (पुरुष-8758, महिला-1694, ट्रांसजेंडर-02) पंजीकृत किए गए हैं।

8. विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):

क. विधिक जागरूकता वेबिनार श्रृंखला के एक भाग के रूप में न्याय विभाग ने 29 सितंबर, 2023 को "श्रम कानून" पर 19वां वेबिनार आयोजित किया और वेबिनार 2,153 प्रतिभागियों तक पहुंचा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, प्रवासन और शरण परियोजना के प्रतिष्ठित वक्ता और जन पहल ने वेबिनार में अपने सत्र का संचालन किया

ख. सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी। (CECOEDECON) जयपुर, राजस्थान ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अधिकारों पर राजस्थान के सिरोही जिले में 10 धानी बैठकें, 39 पंचायत स्तरीय कानूनी जागरूकता सत्र और 6 जागरूकता अभियान आयोजित किए और 1,863 लोगों तक पहुंचे।

ग. जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), मणिपुर ने 72 सामुदायिक प्रमुखों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्राम प्राधिकारियों शिक्षकों और छात्रों के लिए 13 सितंबर 2023 को मणिपुर के कामजोंग जिले के खयांग में बाल यौन शोषण के प्रति प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया ।

घ. अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान मैसूरु, कर्नाटक ने 20-22 सितंबर, 2023 तक जिला पंचायत संसाधन केंद्र, हावेरी, कर्नाटक में 31 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला अध्यक्षों के लिए कानूनी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

****